भारत और पाकिस्तान से सियाचीन को कैसे बचायें?

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक क्षण के लिए सियाचिन विवाद के समाधान के लिए कुछ वादा करनेके बिल्कुल करीब आ गये जब उन्होंने कहा कि वे इस क्षेत्र को शान्ति के पर्वत के रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा कहने के बाद उनके द्वारा दिये गये इस समझौता विरोधी वक्तव्य कि ''भारत सीमा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर सहमत नहीं हो सकता', से ऐसा लगता है कि वे अपने पूर्ववर्ती विचार पर और आगे बढ़ने के बजाय वापस लौट गये। सन् 1984 की दरार के बाद सियाचीन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ बन गया है। पाकिस्तानी सिपाहियों के 1983 में इस क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले यह आदि काल से ही मानवविहीन क्षेत्र था जिसका सबसे बड़ा महत्व यह था कि इसके बर्फके पिघलने से नुब्रा नदी भर जाती थी। परन्तु अब शियाचिन ग्लेशियर ने नये रूप ग्रहण कर लिये हैं जो दोनों देशों में आवेग पैदा करता है। भारत सालटोरो पर्वतश्रेणी (Saltoro ridge) की सुरक्षा की बड़ी कीमत चुकाता है और पाकिस्तान के पास अबतक इतना माद्दा पैदा नहीं हुआ है कि वह पिफर एक बार इसे भारतीय सेना से छीन ले। इसलिए सियाचीन पर भारतीय झण्डा के पहली बार फहराये जाने के सोलह साल बाद भी दोनों देश सियाचीन के बाहर ही लड़ते रहे हैं।

रणनीतिक महत्व के अलावा सियाचीन का भारत के लिए कोई और महत्व नहीं है। नुब्रा घाटी के बीचोबीच पुराना कारवाँ मार्ग (Old Caravan route) सासेर का दर्रे के लिए उत्तर की ओर मुड़ जाता है। सेंसर–ला दर्रा, ससेर मुस्ताध श्रेणी पार करने का एकमात्र रास्ता है। यह काराकोरम के बाहर का ऐसा क्षेत्र है जिसे भारतीय सेना सब सेक्टर नार्थ या एस.एस.एन. कहती है। इसके अंतर्गत (भीतर) दौलत बेग ओल्डी (डी. बी.ओ.) और देप्सांग मैदान आते हैं। एस.एस.एन. जाने का एकमात्र दूसरा रास्ता

शायोक घाटी (Shyok Valley) में जुड़ा गर्मी में खुलने वाला लम्बा रास्ता है। आसान रास्ते की इस कमी के कारण एस.एस.एन. पर स्थित हमारी चौकियों की रक्षा करना कठिन है। अनेक सैन्य विशेषज्ञाों को इस पर विश्वास नहीं है कि चीनी हस्तक्षेप के विरुद्ध बहुत लम्बे समय तक एस.एस.एन. पर कब्जा बनाये रखा जा सकता है। फिर भी सम्पूर्ण सियाचीन क्षेत्र से हट जाने का मतलब नुब्रा घाटी (Nubra Valley) से न केवल पाकिस्तानियों को बल्कि चीनियों को भी सियाचीन पर पहुंचने का आसान रास्ता उपलब्ध कराना होगा। पाकिस्तानियों ने ऐसी अनेक सड़कें भी बना ली हैं जो उन्हें सालतोरो पर्वतश्रेणी (Saltoro Ridge) के बहुत पास पहुँचा देती है। यदि एक बार यह पर्वत श्रेणी उनके कब्जे में आ जाती है तो पर्वतश्रेणी के रास्ते ग्लेशियर तक पहुँचने में ज्यादा मुश्किल नहीं आयेगी। इसी प्रकार यदि चीनियों ने एस.एस.एन. पर नियंत्रण कर लिया तो सासेर–ला (Saser-la) पर नियंत्रण घातक होगा। सियाचीन से भारतीय सेना को वापस बुला लेने का मतलब होगा कि लेह और आक्रमणकारियों के बीच केवल खर्दंग–ला (Khardang-la) दर्रा रह जाएगा। और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारत और पाकिस्तान द्वारा सियाचीन के ऊपर बहुत अधिक खर्च करने के विषय में बहुत अधिक लिखा जा चुका है। यहाँ आर्थिक लागत तो विशाल है ही इसके साथ ही आदमियों की जानों की कीमत भी बहुत अधिक है। यहां दोनों तरफ मिलाकर लगभग दो हजार से अधिक आदमी मारे जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त अन्य सालतोरो पर्वत श्रेणी पर पूरा कर लेती है तब फिर लगभग आठ वर्षों तक वह पुनः उस जगह पर वापस नहीं जा सकती। यह एक कठिन शुल्क है जो इस प्रकार के कार्य से वसूला जाता है। जहां एक ओर हम ये सोच सकते हैं कि इस प्रकार के खर्च का वहन किया जा सकता है वहीं हमें उन अति गंभीर परिणामों के बारे में जरूर सोचना चाहिए जिनके मामले में हमारे प्रयास कमजोर साबित हुए।

जैसे कि सियाचीन का वातावरण बहुत ही कमजोर और अस्वास्थ्यकर है ऐसा सियाचिन और उससे सटे हुए क्षेत्रों में बड़ी संख्या में सैनिकों की उपस्थिति के कारण ग्लेशियर के प्रदूषित हो चुके वातावरण के कारण है। अकेले भारत के पास ग्लेशियर पर सैनिकों की सहायता के लिए एक ब्रिगेड है। दोनों देशों के पास बारहो महीने वर्फ से ढंकी रहने वाली चोटियों पर युद्ध करने वाली कम–से–कम एक बटालियन है। इसका मतलब यह है कि पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील इस ग्लेशियर पर कुल मिलाकर लगभग बारह सौ आदमी रहते हैं। तब इसके बेहद कमजोर पारिस्थितिकी पर इतने अधिक आदमियों के स्थायी रूप से रहने के परिणामों की कल्पना की जा सकती है।

साल भर शून्य से भी नीचे रहने वाले यहां के तापमान में किसी भी प्रकार का जैव–निम्नीकरण सम्भव नहीं है और वहां पर जैविक कूड़े को खानेवाले कीड़े भी नहीं हैं। वहां हैं तो केवल ढेर सारे भारतीय और पाकिस्तानी। परिणामस्वरूप सारे कूड़े को धातु के बने ड्रमों में भरा जाता है और उन्हें हिम–दरारों में डाल दिया जाता है। यहां केवल मनुष्यों द्वारा उत्पन्न ठोस कूड़े की मात्रा प्रतिदिन हजारो किलोग्राम से अधिक हो जाएगी। अनुमानतः धातु के एक ड्रम में सौ किलो कुड़ा आता है। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों तरफ के लोग एक साथ मल से पूरी तरह भरे हुए कम से कम दस ड्रम प्रति दिन हिम–दरारों में डालते हैं। प्रति वर्ष यह 3500–4000 ड्रम हुआ। हमलोग साथ–साथ वहाँ डेढ़ दशक से अधिक समय से रह रहे हैं। इसका का मतलब यह हुआ कि वहां बर्फ के नीचे जमे हुए मल के 55–60 हजार ड्रम इस इंतजार में बन्द पड़े हुए हैं कि एक दिन नुब्रा नदी में बहकर नीचे आ जाएंगे।

जरा पाठक स्थिति की भयावहता का अनुमान करें और वहां के क्षेत्र से इसे जोड़ कर देखें। कल्पना करें कि 10–12 फीट की गहराई में ड्रम कतार में लगे हुए हैं। ये 4.5 किलोमीटर के क्षेत्र में इंडिया गेट से विजय चौक के बीच राजपथ के नीचे फैले हुए हैं। इसमें उन तमाम प्रकार के टेट्रापैकों, खाली बोतलो, युव्द्ध के उपकरणों के खोलों, पैकेजिंग के सामानों और अन्य कूड़ों की गणना नहीं की गई है जो उसी प्रकार दबा

दिये जाते हैं। स्पष्ट है कि इन चीजों का ढेर सियाचीन को नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। यह लेखक लम्बे समय तक सियाचीन से हमारी सेनाओं की वापसी का विरोधी रहा है। लेकिन साक्ष्यों के द्वारा जो पता चल रहा है वह हमें नये सिरे से विचार करने पर मजबूर कर रहा है। वियतनाम में अमेरिकी कमाण्डर ने एक बार वियतनामी शहर को नष्ट कर देने या उसे बचा लेने के बारे में कुछ कहा था। क्या हम सियाचीन ग्लेशियर के सम्बन्ध में वही नहीं कर रहे हैं?

बहुत लम्बा समय नहीं बीता है जब सियाचीन ग्लेशियर की लम्बाई 82 किलोमीटर हुआ करती थी। 1985 में लड़ी गई घातक लड़ाई ने सीधे तौर पर इसकी लम्बाई को कई किलोमीटर कम कर दी। विशाल प्रकृति पर पड़ने वाले अपरिवर्तनीय और गम्भीर परिणामों को देखते हुए हम इसकी लम्बे समय तक अनुमति नहीं दे सकते हैं लेकिन दोनों तरफ की सामान्य तरीके से होने वाली वापसी उपयुक्त हल नहीं है। किसी भी हल को भारत की युद्ध सम्बंधी अपेक्षाओं की जिम्मेदारी लेनी होगी। दो सैनिक क्षेत्रों (चीन एवं पाकिस्तान) का ध्यान रखना होगा और अपने क्षेत्र की दावेदारी के लिए तैयार रहना होगा।

लेकिन थोड़ी–सी दूरदर्शिता और कल्पना का उपयोग कर हम इन रास्तों की प्राकृतिक तबाही की समस्या का हल निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस क्षेत्र में फैले हुए आदमियों की संख्या को बहुत ज्यादा घटाना होगा। मान लें कि भारत और पाकिस्तान शिष्टता और सद्भाव का परिचय देते हुए साल्टोरो और इसके विपरीत खड़े श्रेणियों से अपने सैनिकों को वापस बुला लेते हैं पर 'विश्वास करो किन्तु सत्य की जांच करो' सैनिक नियन्त्रण का सर्वमान्य कथन है। हम अपने भगवान पर भी इस बात के लिए विश्वास नहीं कर सकते कि मौका मिलने पर वह दुश्मन को नुकसान नहीं पहुंचायेंगें। भारत और पाकिस्तान को दोनों ओर से आसान और न दिखाई पड़ने वाले प्रवेश को रोकने के लिए एक बिल्कुल सुरक्षित व्यवस्था की आवश्यकता है। इस ओर

पहला कदम यह होगा कि दोनों देश दुर्गम स्थानों तक पहुंचाने वाली सड़कों को नष्ट कर दें। विश्वभर के प्रकृति संरक्षक इसका अनुमोदन करेंगे और दोनों देशों को सद्भाव निर्माण के लिए ऐसे अनुमोदनों की जरूरत होगी। इसके बाद एक–दूसरे के प्रति मन में बैठे भयानक डर को शान्त करने और विश्वास जगाने के लिए सीमा पर संयुक्त निगरानी करने वाले सिपाहियों की व्यवस्था करनी होगी। अमेरिका को दलाली का अवसर दिये बगैर और उनके हाथों की कठपुतली बने बगैर भारत और पाकिस्तान ऐसा कर सकते हैं।

घाटी के सैनिकों की पूर्ण वापसी सासेर मुस्ताग श्रेणी और इसके आगे स्थित एस.एस. एन. से जुड़ी भारतीय सुरक्षा के प्रति निश्चिंत नहीं कर देगी। भारत की सुरक्षा का सम्बन्ध चीन से भी उसी प्रकार जुड़ा हुआ है और इसके लिए जरूरी होगा कि ससेर–ला दर्रे के पुराने कारवाँ मार्ग से चीन भी अपने सारे सैनिकों और सामान के साथ नीचे उतर जाएं। इस सारी व्यवस्था को सहज और आसान बनाने के लिए इस मार्ग पर कुछ स्थायी चौकियों के निर्माण की जरूरत होगी। सम्भव है, ग्लेशियर पर भी चौकी बनानी पड़े। लेकिन इसके लिए साल्टोरो श्रेणी क्षेत्र को सैनिकों से भरने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके द्वारा पाकिस्तान को यह सुविधा होगी कि वह जिन स्थितियों का सामना कर रहा है उनसे बचे। अब हमें एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत है जो एक–दूसरे को आश्वस्त कर सकें।

यह दोनों पक्षों के सहयोग से विकसित होगा। एक हल दोनों देशों द्वारा बारी–बारी से क्षेत्र की आकाशीय निगरानी करना हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी खास दिन भारतीय और पाकिस्तानी हवाई जहाज साथ–साथ उड़कर फोटो सर्वेक्षण कर सकते हैं या दोनों देश निश्चित क्षेत्रों में हथियार विहीन जहाजों के उड़ान की अनुमति दे सकते हैं और स्वतंत्रतापूर्वक पर्वतीय श्रेणियों निःसैनिकीकरण स्थिति की जाँच कर सकते हैं तथा एक–दूसरे के क्षेत्रों की सैनिक स्थिति का अध्ययन भी कर सकते हैं। यह भी

सम्भव है कि दोनों देशों के लोग एक ही हवाई जहाज से निरीक्षण करें और जो समस्या दिखाई दे उसपर विचार–विमर्श कर उसे तत्काल हल कर लें। इन सभी प्रारूपों के लिए संयुक्त हवाई अड्डा, हेलीपैड का उपयोग किया जा सकता है। दोनों पक्ष स्पष्टीकरण, बातचीत और हवाई फोटोग्राफी के मूल्यांकन के लिए एक मिलन स्थल साथ बैठकर सहजता से कार्य कर सकते हैं।

अगले कदम के रूप में ग्लेशियर को संरक्षित क्षेत्र बनाना होगा जिसपर दोनों देशों का संयुक्त प्रभुत्व होगा और वही ट्रैकिंग और पर्वतारोहण अभियानों की स्वीकृति और अनुमोदन का कार्य देखेगी। तब इस क्षेत्र की स्वच्छता और सौन्दर्य की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। वर्षों से इकट्ठा हुए कूड़े की सफाई का खर्चा काफी अधिक होगा। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति इस बात पर सहमत होगा कि किसी स्थान को गन्दा करने की तुलना में उसे साफ करने के लिए किया गया खर्च बेहतर एवं स्वीकार्य है। अगर हम इन बातों पर सहमत नहीं हो सकते तो यह काव्यात्मक न्याय होगा कि जमे हुए मल गर्मी में पानी के साथ बहते हुए नीचे आयेंगे और दोनों अर्थात् भारतीय और पाकिस्तानी एक साथ अपने ही मल घुले जल में स्नान करेंगे और इसी बीच उनके हाथों में उन्हीं का मल होगा।

MOHAN GURUSWAMY
3515 DLF 4, Gurgaon 122002, Haryana
Email: mguru@satyam.net.in